

भारत सरकार  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 27

बुधवार, 2 फरवरी, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली

27. श्री ज्ञानेश्वर पाटिल:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) अब तक राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से कितने विभागों को जोड़ा गया है; और  
(ख) राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली की परिभाषा और इसका कार्यकरण तथा ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री सोम प्रकाश)

(क) और (ख): उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर पोर्टल को राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की। देश में सभी विनियामक अनुमोदन और सेवाएं प्राप्त करने के लिए वन-स्टॉप शॉप के रूप में परिकल्पना की गई है। एनएसडब्ल्यूएस [[www.nsws.gov.in](http://www.nsws.gov.in)] को 22 सितंबर, 2021 को माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा सॉफ्ट-लॉन्च किया गया था।

यह राष्ट्रीय पोर्टल, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों की मौजूदा मंजूरी प्रणालियों को उनके मौजूदा आईटी पोर्टलों को बाधित किए बिना एकीकृत करता है।

वर्तमान में, 19 मंत्रालयों/विभागों के आईटी पोर्टल और 13 राज्यों के सिंगल विंडो सिस्टम को एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल से जोड़ दिया गया है। जोड़े गए मंत्रालयों/विभागों और राज्यों की सूची **अनुबंध** पर देखी जा सकती है।

निवेश पूर्व सलाह, अपने अनुमोदन को जानें (नो यौर अप्रूवल) (केवाईए) मॉड्यूल को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और विभिन्न राज्यों के 3000 से अधिक अनुमोदनों के साथ शुरू किया गया है।

एकीकृत आवेदन प्रपत्र (यूएफ) को संभावित निवेशकों के लिए एक सामान्य आवेदन प्रपत्र के रूप में तैयार किया गया है और यह एक डायनेमिक प्रपत्र है जो सभी निवेशकों के मूल विवरण को रखता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निवेशक से मांगी जा रही जानकारी का दोहराव नहीं हुआ है।

केंद्रीय प्रलेखन कोष, एक व्यक्तिगत दस्तावेज़ स्टोरेज सुविधा है जो निवेशकों को आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने और प्रत्येक अनुमोदन की आवश्यकता के अनुसार उन्हें प्रपत्र में संलग्न करने की सुविधा प्रदान करता है।

एक बार जब निवेशक प्रपत्र को पूरा कर लेते हैं और सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा कर देते हैं, तो उन्हें किए गए सभी आवेदनों के अनुरूप एनएसडब्ल्यूएस पर भुगतान सेवा के माध्यम से भुगतान करने के लिए कहा जाता है। एक बार एनएसडब्ल्यूएस पर आवेदन जमा करने के बाद, निवेशक डैशबोर्ड के माध्यम से निवेशक आवेदन की स्थिति की निगरानी करने में सक्षम होते हैं। एनएसडब्ल्यूएस पर अंतिम अनुमोदन की स्थिति प्राप्त करने के अलावा, निवेशक आवश्यकता के अनुसार प्रश्न और शिकायत भी कर सकते हैं।

\*\*\*\*\*

अनुबंध

**दिनांक 02.02.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 27 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

**एनएसडब्ल्यूएस से जुड़े मंत्रालय/विभाग:**

1. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
3. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
4. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
5. उपभोक्ता मामले विभाग
6. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एफएसएसएआई और सीडीएससीओ)
7. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
8. वाणिज्य विभाग
9. दूरसंचार विभाग
10. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
11. विद्युत मंत्रालय
12. रेल मंत्रालय
13. बायो टेक्नोलॉजी विभाग
14. राजस्व विभाग
15. नागर विमानन मंत्रालय
16. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
17. मत्स्य पालन विभाग
18. वस्त्र मंत्रालय
19. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

एनएसडब्ल्यूएस से जुड़े राज्य:

1. गोवा
2. गुजरात
3. हिमाचल प्रदेश
4. ओडिशा
5. उत्तर प्रदेश
6. उत्तराखंड
7. पंजाब
8. कर्नाटक
9. मध्य प्रदेश
10. आंध्र प्रदेश
11. तेलंगाना
12. महाराष्ट्र
13. तमिलनाडु

\*\*\*\*\*